

जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेरिस समझौते की वफ़िलता

प्रलिस के लिये:

[पेरिस समझौता](#), भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निरधारति योगदान लक्ष्य, [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय](#), [स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट](#)

मेन्स के लिये:

हू इज़ टपिगि द स्केल रिपोर्ट: IPES

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है।

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर चल रही वैश्विक वार्ता का केंद्रीय बटु है, इस पर वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किये गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते का प्रदर्शन:

जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता:

- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरांत पछिले आठ वर्ष (2015-2022) विश्व स्तर पर लगातार सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।
 - यदि पछिले तीन वर्षों में [ला नीना](#) की घटना नहीं हुई होती, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी।
 - अद्यतन 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य (जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है) के संदर्भ में विश्व स्तर पर अद्यतन **राष्ट्रीय स्तर पर निरधारति योगदान (NDC)** संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं है।
 - जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट के लिये मुख्य रूप से ज़िम्मेदार कारक है, यह पेरिस समझौते के तहत इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतिबद्धता में सफल नहीं रहा है।
 - जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिये न तो **NDC** और न ही **आपदा जोखिम में कमी और जलवायु जोखिम प्रबंधन योजनाएँ** कारगर रही हैं।

सुझाव:

- [पेरिस समझौते](#) के पूरक हेतु **जीवाश्म ईंधन संधि के रूप में एक नया वैश्विक ढाँचा पेश किया जाना चाहिये**।
- अधिकांश औद्योगिक और उत्सर्जन उत्पादक देशों को पेरिस समझौते की शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य किया जाना चाहिये।
- तीव्र और तेज़ कार्बन कटौती के साथ त्वरित जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि साधन, सूचना और समाधान मौजूद हैं।
- अनुकूलन और लचीलापन में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर देशों और समुदायों के लिये जिन्होंने संकट पैदा करने में कम-से-कम योगदान दिया है।**

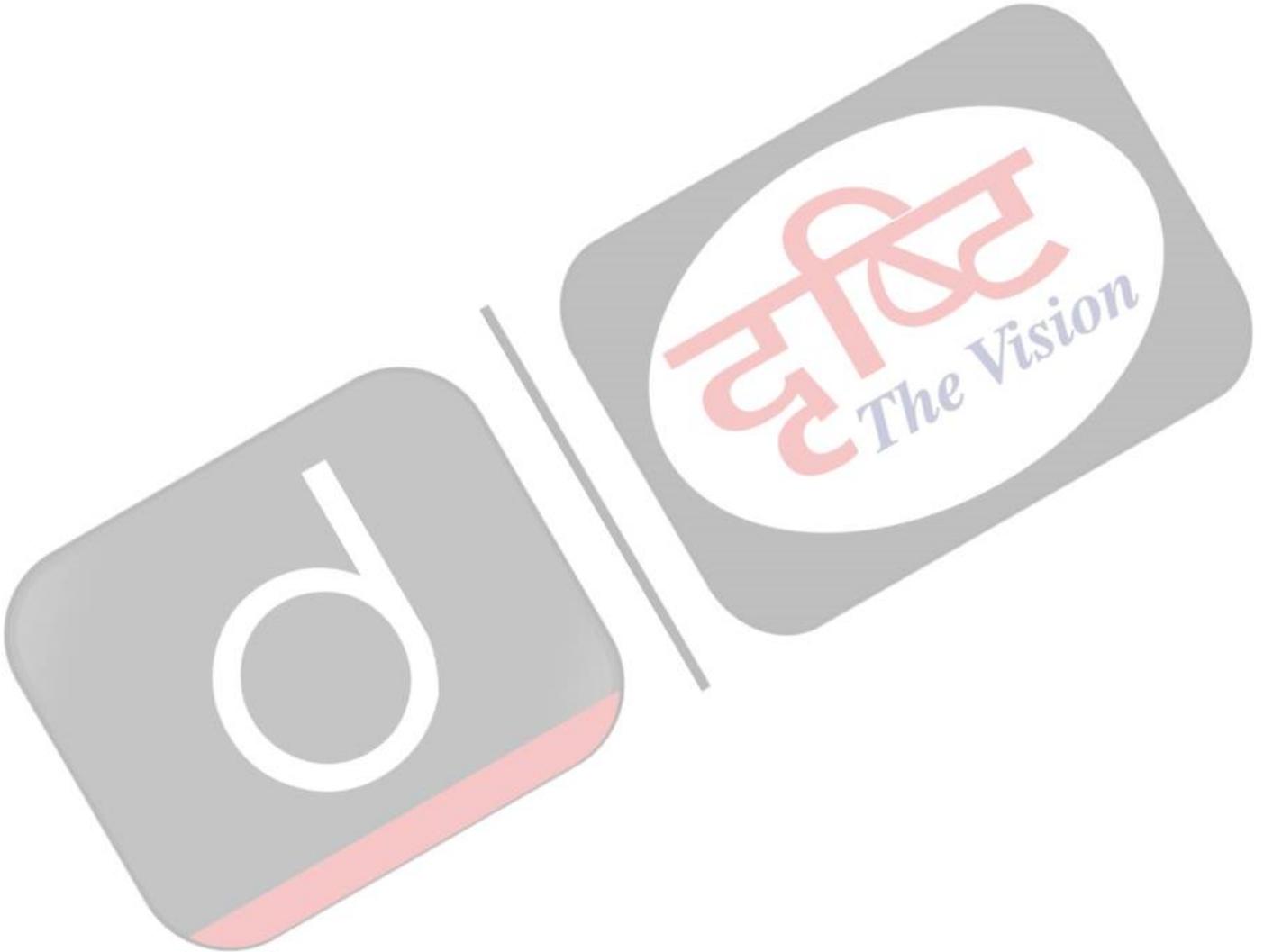
जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता:

- यह [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय \(United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC\)](#) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से नीचे तक सीमित करना है, साथ ही

वास्मगि को 1.5°C तक सीमति करने का लक्ष्य है ।

- इसने [क्योटो प्रोटोकॉल](#) के रूप में परसदिध पूर्व जलवायु परिवर्तन समझौते का स्थान लिया है ।
- पेरसि समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने और जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के अपने परयासों में वकिसशील देशों को सहायता प्रदान करने हेतु एक साथ काम करने के लिये देशों के संदर्भ में रूपरेखा तैयार करता है ।
- पेरसि समझौते के तहत **प्रत्येक देश** को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिये अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए उसे **प्रत्येक 5 वर्ष में NDC को प्रस्तुत और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है** ।
 - NDC, देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने हेतु लिया गया एक वचनपत्र है ।
 - [भारत के अद्यतन NDC:](#)

//



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????:

प्रश्न. "अभीष्ट राष्ट्रीय नरिधारति अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions)" पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- युद्ध-प्रभावति मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनरवास के लयि यूरोपीय देशों द्वारा दयिा गया वचन
- जलवायु परविरतन का सामना करने के लयि वशिव के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना
- एशयिाई अवसंरचना नविश बैंक (एशयिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा कयिा गया पूंजी योगदान
- धारणीय वकिस लक्ष्यों के बारे में वशिव के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना

उत्तर : (B)

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरसि में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

- समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कयि थे और यह 2017 में प्रभावी होगा ।
- समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमति करना है ताक इस सदी के अंत तक औसत वैश्वकि तापमान में वृद्धिपूर्व-औद्योगकि स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो ।
- वकिसति देशों ने ग्लोबल वार्मगि में अपनी ऐतहासकि ज़मिमेदारी को स्वीकार कयिा और वकिसशील देशों को जलवायु परविरतन से नपिटने में मदद करने के लयि वर्ष 2020 से प्रतविरष \$1000 बलियिन दान करने के लयि प्रतबिद्ध हैं ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- केवल 1 और 3
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. 'जलवायु परविरतन' एक वैश्वकि समस्या है । जलवायु परविरतन से भारत कैसे प्रभावति होगा? भारत के हमिलयी और तटीय राज्य जलवायु परविरतन से कैसे प्रभावति होंगे? (2017)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परणामों का वर्णन कीजयि । इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतबिद्धताएँ कया हैं? (2021)

स्रोत: डाउन टू अर्थ